उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 20 | 16-31 अक्टूबर 2025 | ₹ 20/-

बिहार विधानसभा चुनाव में उर्दू अखबारों की भूमिका

- कर्नाटक में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक
- पाकिस्तान द्वारा भारत में उत्पात मचाने की साजिश
- गाजा युद्धविराम समझौता खतरे में
- पुर्तगाल में बुर्का पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव में उर्दू अखबारों की भूमिका 04
कर्नाटक में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक 09
आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकवादी गिरफ्तार 11
पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर विवाद 13
औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव 15

विश्व

पाकिस्तान द्वारा भारत में उत्पात मचाने की साजिश 17
पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के खिलाफ अभियान 19
बांग्लादेश में जाकिर नाइक के स्वागत की तैयारी 20
पुर्तगाल में बुर्का पर प्रतिबंध 21
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की जेल 22

पश्चिम एशिया

गाजा युद्धविराम समझौता खतरे में 24
तुर्की द्वारा कुवैत, कतर और ओमान के साथ समझौते 26
तुर्की द्वारा विदेशों से लड़ाकू विमानों की खरीद 27
सऊदी अरब द्वारा उमरा के लिए 40 लाख वीजा जारी 28
सूडान के गृहयुद्ध में 1500 लोगों की मौत 29

सारांश

बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में अधिकांश उर्दू अखबारों का विश्लेषण भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ है। उनका कहना है कि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है और वे कम-से-कम 60 सीटों पर किसी भी पार्टी को जीत दिलाने में सक्षम हैं। हालांकि, इसके बावजूद दोनों गठबंधनों में से किसी ने भी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें नहीं दी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार पार्टी ने सिर्फ चार मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। वहीं, भाजपा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है।

उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वक्फ विधेयक का विरोध न किए जाने का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि उनकी इस हरकत से मुसलमानों के हमदर्द होने के उनके दावे की कलई खुल गई है। उर्दू अखबारों ने शिकायत की है कि विपक्षी महागठबंधन ने 18 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या को नजरअंदाज करके विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। यह मुसलमानों के साथ घोर अन्याय है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय का यह फैसला कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए करारा झटका बताया जा रहा है। कहा जाता है कि यह प्रतिबंध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे के दबाव पर लगाया गया था।

पाकिस्तान भारत विरोधी अपनी नीति से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश, जॉर्डन और तुर्की का दौरा किया था। पाकिस्तान का यह प्रयास है कि इन मुस्लिम देशों को भारत विरोधी फ्रंट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रयास है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो सैन्य समझौता किया था उसमें अन्य मुस्लिम देशों को भी शामिल किया जाए। इस समझौते में यह व्यवस्था है कि अगर कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। हालांकि, हाल के पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में सऊदी अरब का रुख पाकिस्तान की आशा के अनुरूप नहीं रहा। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, तुर्की और कतर के प्रयास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता तो हो गया, लेकिन यह कब तक टिक पाएगा यह कहना बेहद मुश्किल है।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आतंकवाद और अलगाववाद की ज्वाला भड़काना है। इस संबंध में हाल ही में पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के कुछ आतंकवादी बांग्लादेश गए हैं। इनका लक्ष्य भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल और हमास के बीच जो समझौता करवाया था वह खतरे में पड़ गया है। गाजा इलाके में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। इन हमलों में लगभग 150 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने यह वायदा किया था कि वह अपने हथियार डाल देगा, लेकिन अब वह इसके लिए तैयार नहीं है।

बिहार विधानसभा चुनाव में उर्दू अखबारों की भूमिका

उर्दू अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण एकपक्षीय दृष्टिकोण से किया है। अधिकांश उर्दू अखबारों का रुख एनडीए विरोधी है। इन अखबारों ने राज्य के मुसलमानों से अपील की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर एनडीए विरोधी दलों के पक्ष में मतदान करें ताकि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सके। खास बात यह है कि उर्दू अखबारों ने इसी तरह का अभियान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी चलाया था, लेकिन वह बेअसर रहा। महाराष्ट्र के मुस्लिम मतों में विभाजन हुआ और भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। हालांकि, उर्दू मीडिया को यह भी शिकायत है कि किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 18 प्रतिशत है। उर्दू अखबारों का दावा है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 60 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मुसलमानों के हाथ में है। कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय में शिकायत है कि विपक्षी महागठबंधन ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उपमुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है। उर्दू अखबारों का पूरा जोर इस बात पर है कि मुस्लिम मत विपक्षी गठबंधन को ही मिले। इन उर्दू अखबारों ने मुसलमानों को आगाह किया है कि वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी को वोट देकर मुस्लिम मतों को विभाजित न करें।

बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने चार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने भी एक मुस्लिम उम्मदीवार को मैदान में उतारा है। जबकि भाजपा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। दूसरी ओर, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जबकि सीपीआई (एमएल) ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची में

भले ही 18 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कभी भी सात प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।

समाचारपत्र ने कहा है कि विधानसभा में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व का एक कारण यह भी है कि पिछले दो दशक में राज्य में कोई भी सर्वमान्य मुस्लिम नेता नहीं उभर सका। बिहार के उत्तरी और पूर्वोत्तर जिलों जैसे

25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें से 23 मुसलमान हैं।

अखबार-ए-मशरिक (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में बिहार विधानसभा में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हों और मुस्लिम विरोधी पार्टियों को हराने में सक्षम उम्मीदवारों को वोट दें। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को अपना अधिकार हासिल करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। समाचारपत्र ने दावा किया है कि फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधायकों में से 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन जब अक्टूबर-नवंबर 2005 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 16 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए। समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि मुसलमान नीतीश कुमार के सुशासन के फरेब में आ गए। हालांकि, उनकी भूमिका हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है। वहीं, 2010 में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन बना तो मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, लेकिन 2020 में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 19 रह गई। इस तरह से बिहार में

किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सिवान और पूर्वी चंपारण में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन उन्होंने आपसी मतभेदों के कारण मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय हमेशा हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिए। एआईएमआईएम भी सीमांचल क्षेत्र में कोई सर्वमान्य नेतृत्व तलाश करने में विफल रही है। जबकि कांग्रेस के तारिक अनवर, शकील अहमद खान, मुदासिर शम्स, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली, तनवीर हुसैन और कारी सुहैब राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वे मुसलमानों में अपनी पैठ नहीं जमा पाए हैं। इसी तरह से जेडीयू में भी कई मुस्लिम चेहरे मौजूद हैं, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वे उभर नहीं सके।

अवधनामा (26 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से अपील की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट दें, क्योंकि नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन कर रखा है। भाजपा की मुस्लिम दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि आरजेडी ने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया और उसने मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हालांकि, मुसलमानों के पास भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

सियासत (16 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में जन सुराज पार्टी के बारे में मुसलमानों को सतर्क किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रशांत किशोर के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुसलमानों को आगामी चुनाव में सोच समझकर वोट देना चाहिए। मुसलमानों को प्रशांत किशोर की चिकनी-चुपड़ी बातों से बचना चाहिए।

एतेमाद (29 अक्टूबर) ने कहा है कि एआईएमआईएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की नजरें मुस्लिम मतों पर टिकी हुई हैं। वे भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं। इन पार्टियों में यह ताकत नहीं है कि वे भाजपा और जेडीयू को चुनाव में हरा सकें। असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत की है कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं दिए हैं। हालांकि, बिहार में मुस्लिम जनसंख्या 18 प्रतिशत है। अगर मुसलमान एकजुट होकर मुसलमानों की हमदर्द पार्टी एआईएमआईएम को अपने वोट देते हैं तो एक मुस्लिम व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की आड़ में मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह को यह बताना चाहिए कि एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है। ओवैसी ने पूछा कि बीएसएफ की मौजूदगी के बावजूद घुसपैठ कैसे हो रही है। जबकि बीएसएफ स्वयं अमित शाह के मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

उर्दू टाइम्स (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से अपील की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के हथकंडों से सचेत रहें। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा महागठबंधन के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठा सकती है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास महागठबंधन की आशाओं पर पानी फेर सकता है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे एकजुट होकर अपने वोट ऐसे उम्मीदवारों को दें, जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। मुसलमानों को यह प्रयास करना चाहिए कि उनका शत-प्रतिशत मतदान हो।

हमारा समाज (29 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों को सतर्क रहने को कहा है ताकि विभिन्न दलों में उनके मतों का विभाजन न हो। मुस्लिम मतों में विभाजन का लाभ भाजपा को होगा। समाचारपत्र ने आलोचना की है कि महागठबंधन ने उपमुख्यमंत्री के रूप में किसी मुस्लिम नाम की घोषणा नहीं की है। इसके कारण मुसलमानों में यह भावना घर कर रही है कि उनके वोटों से सरकारें तो बनती हैं, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती। भाजपा ने मुस्लिम मतों में विभाजन के लिए कई कथित मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतार दिया है। ये नेता मस्जिदों और मदरसों का दौरा कर रहे हैं और 'सबका साथ, सबका विकास' के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है और 60 सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में हैं। मुस्लिम मतदाता सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा,

दरभंगा, अररिया और भागलपुर में राजनीति का रुख बदलने की स्थिति में हैं। पिछली बार 80 प्रतिशत मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, लेकिन इस बार मुस्लिम मतों में विभाजन का खतरा है। कई मुस्लिम संगठन बरसाती मेंढक की तरह पैदा हो गए हैं। इस खेल के पीछे भाजपा का हाथ है, जो मुस्लिम मतों को विभाजित करके अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाना चाहती है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर स्वयं को मुसलमानों के हमदर्द के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। वे मुसलमानों को यह अहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वे फिर से सत्ता में आए तो मुसलमानों के साथ पूरी तरह से न्याय करेंगे। हकीकत यह है कि मुसलमान भले ही सेक्युलर पार्टियों को समर्थन करते रहे हैं, लेकिन उनका एक वर्ग ऐसा भी था जो नीतीश कुमार को मुसलमानों का दोस्त मानता था और उन्हें अपना मत देता था। अब नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने से उनके मुस्लिम समर्थक उनसे दूर हो रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में अपना रुख बदल लिया है। यही कारण है कि उन्होंने वक्फ विधेयक का न तो सदन में विरोध किया और न ही भाजपा पर दबाव डाला कि वह इस विधेयक को वापस ले ले। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सेक्युलर पार्टियों को जीत दिलाते हैं या विभाजित होकर एनडीए को फिर से सत्ता में लाते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि एनडीए ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से परहेज किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि जेडीयू ने भी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया है और उसने सिर्फ चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इससे साफ है कि नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टियां भाजपा के दबाव में मुसलमानों को हाशिए पर रखना चाहती हैं। भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने की जरूरत नहीं समझी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि टिकट बंटवारे के समय किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदार को मैदान में नहीं उतारा है। जबकि जेडीयू ने सिर्फ चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान

में उतारा है। 2020 में पार्टी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि, एनडीए की एक अन्य सहयोगी पार्टी एलजेपीआर ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को अपना टिकट जरूर दिया है। इसके कारण मुसलमानों में भारी नाराजगी है। वहीं, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं दिए हैं। हालांकि, आरजेडी ने 18, सीपीआई (एमएल) ने दो और कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जबकि बिहार की राजनीति में आई नई पार्टी जन सुराज ने कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को अपने टिकट दिए हैं, लेकिन इसके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि उसने मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए यह खेल खेला है।

अजीब बात है कि सेक्युलरिज्म का दंभ भरने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी कई ताकतवर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना जरूरी नहीं समझा। बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है, इसलिए कम-से-कम 44 सीटों पर मुसलमानों की मजबूत दावेदारी बनती है। राज्य की 243 सीटों में से 87 सीटों पर मुसलमानों की जनसंख्या 20 प्रतिशत से भी अधिक है। जबकि 47 सीटों पर लगभग 15 प्रतिशत है। हालांकि, मुसलमान अभी तक महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम की मौजूदगी के कारण उनके मतों में विभाजन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में मुसलमानों की हैसियत शून्य हो जाएगी।

इंकलाब (31 अक्टूबर) में प्रकाशित एक लेख में मुसलमानों से अपील की गई है कि वे एकजुट होकर सेक्युलर पार्टियों के समर्थन में शत-प्रतिशत मतदान करें। अगर उनके वोट विभाजित हो गए तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा और बिहार में भी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जैसा मुस्लिम विरोधी माहौल बनेगा। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मदरसों पर ताले लगाए जाएंगे और बेगुनाहों के घरों पर बुलडोजर चलेंगे। सवाल बिहार में शासन का नहीं, बल्कि मुसलमानों के अस्तित्व का है, इसलिए मुसलमानों को हर हालत में एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को धूल चटानी होगी। एक-एक मतदाता चाहे वे महिला हों या पुरुष उन्हें अपने घरों से निकलना होगा और मुसलमानों के अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होकर मतदान करना होगा। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वे मतदान के मामले में सक्रिय

नहीं होतीं। मुसलमानों को बिहार की चुनावी स्थिति पर पैनी नजर रखनी होगी ताकि वोट भी पड़े और किसी के मिलीभगत से वोटों की चोरी भी न हो। बता दें कि यह लेख मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह है, जो मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया के उप प्रबंधक हैं।

कौमी भारत (20 अक्टूबर) ने आरोप लगाया है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 32 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी का लक्ष्य मुस्लिम मतों को विभाजित करना है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि ओवैसी के पास देश के मुसलमानों की भलाई का कोई विजन नहीं है। वे संसद में जो नौटंकी करते हैं उससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे मुस्लिम विरोधी ताकतों को नया जीवन मिलता है। बिहार के चुनाव में मुस्लिम मतों को विभाजित करने के लिए तीसरे मोर्चे के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, जिनमें एआईएमआईएम, जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। साफ है कि इन पार्टियों को मुस्लिम मतों को विभाजित करने के लिए मैदान में उतारा गया है ताकि मुस्लिम विरोधी ताकतें फिर से सत्ता में आ जाएं। इसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को एकजुट होकर सेक्युलर पार्टियों के पक्ष में मतदान करना चाहिए। अगर मुस्लिम वोट विभाजित हो गए तो एनडीए फिर से सत्ता में आ जाएगी।

इंकलाब (30 अक्टूबर) ने आलोचना की है कि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है, लेकिन कथित सेक्युलर पार्टियों ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को उपमुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। हैरानी की बात है कि 18 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या को नजरअंदाज करके वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे साफ है कि महागठबंधन के मुसलमानों के प्रति इरादे नेक नहीं हैं।

कर्नाटक में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक

सहाफत (29 अक्टूबर) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को एक करारा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने राज्य सरकार, गृह विभाग और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि 'पुनशचैतन्य सेवा समस्थे' नामक संगठन ने 18 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा जारी उस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें बिना अनुमति के 10 से अधिक लोगों की सभा आयोजित करने पर रोक

लगा दी गई थी। इस आदेश में सड़कों, पार्कों, मैदानों और झीलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों की सभा पर रोक लगाई गई थी। राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित ठहराया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार संविधान की धारा 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(बी) (शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता) के तहत दिए गए अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि कोई भी सरकारी आदेश संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। अदालत के इस आदेश से आरएसएस को बड़ी राहत मिली है। जबकि इस मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आरएसएस हमेशा से अपने कार्यक्रम और मार्च शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करता रहा है। राज्य सरकार का यह फैसला कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे की साजिश है।

गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों की मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य आरएसएस की शाखाओं और पथ संचलन पर प्रतिबंध लगाना था। राज्य सरकार का यह फैसला तब सामने आया है जब कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकारी संपत्ति पर आरएसएस द्वारा आयोजित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह फैसला राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया गया है। जबकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने बचाव में दावा किया था कि 2013 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि स्कूल परिसरों और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों तक ही सीमित होना चाहिए।

एक अन्य समाचार के अनुसार एक पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार 12 अक्टूबर को आरएसएस का गणवेश पहनकर संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया था। प्रवीण कुमार ने इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य प्रशासनिक

न्यायाधिकरण में अपील की थी। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य एसवाई वटवती की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी करके प्रवीण कुमार के निलंबन पर रोक लगा दी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार चित्तपुर के तहसीलदार ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर पथ संचलन की अनुमति नहीं दी थी। चित्तपुर निवासी अशोक पाटिल ने जिला प्रशासन के इस फैसले को उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ में चुनौती दी थी। अब उच्च न्यायालय ने संघ को राहत देते हुए 2 नवंबर को पथ संचलन की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह मार्च 19 अक्टूबर को निकाला जाना था। हालांकि, इससे पहले ही सरकारी अधिकारियों ने चित्तपुर में भगवा झंडे, पोस्टर और बैनर हटा दिए थे। गौरतलब है कि चित्तपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे करते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरएसएस की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करके कर्नाटक सरकार को भारी झटका दिया है। आरएसएस के विस्तार को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर अदालत के इस फैसले से पानी फिर गया है। यह प्रतिबंध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के दबाव पर लगाया गया था। समाचारपत्र का कहना है कि इस प्रतिबंध को चुनौती आरएसएस ने नहीं, बल्कि एक अन्य संगठन ने दी थी।

आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकवादी गिरफ्तार

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और भोपाल में छापा मारकर कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मोहम्मद अदनान और अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार मोहम्मद अदनान सीरिया स्थित एक हैंडलर के जरिए आईएसआईएस के वर्तमान खलीफा अबू हाफ्स अल-हाशिमी अल-कुरैशी के संपर्क में आया था। पुलिस ने इस संबंध में एक वीडियो भी बरामद किया है। इस वीडियो में मोहम्मद अदनान आईएसआईएस की पोशाक में इस संगठन में शामिल होने की शपथ ले रहा है। पुलिस का दावा है कि इन आतंकवादियों ने दिवाली और दशहरे के मौके पर देशभर में आत्मघाती हमला करने की योजना बनाई थी। इराक से ऑनलाइन प्रशिक्षित ये दोनों आतंकवादी सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती करते थे।

19 वर्षीय मोहम्मद अदनान उर्फ अबू मुहरिब, पुत्र सलीम खान दिल्ली के सादिक नगर का रहने वाला है। जबकि 20 वर्षीय अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद, पुत्र गुलफाम मियां भोपाल का रहने वाला है। अबू मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उसे भोपाल के एक व्यक्ति ने आईएसआईएस

में भर्ती किया था। पुलिस ने दिल्ली के मोहम्मद अदनान के घर पर छापा मारकर तीन मोबाइल जब्त किए हैं। इनमें आईएसआईएस से जुड़ी सामग्री और तस्वीरें मिली हैं। इसके अतिरिक्त रिमोट डेटोनेशन सिस्टम, प्लास्टिक बम, मोलोटोव कॉकटेल बनाने के निर्देश, एक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। बताया जाता है कि इस गिरोह ने इंस्टाग्राम पर वाराणसी के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि इस न्यायाधीश ने ज्ञानवापी का वीडियो सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया था।

कौमी भारत (25 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने वाराणसी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को परिवार सहित मारने की धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के खिलाफ एक फैसला सुनाया था। कुशवाहा ने कहा कि भोपाल से गिरफ्तार अदनान खान को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। इन आतंकवादियों ने आईएसआईएस के इराक स्थित मुख्यालय से बम बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था। प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है।

सहाफत (31 अक्टूबर) के अनुसार पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने दिवाली के मौके पर दक्षिण दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले शॉपिंग मॉल और एक सार्वजनिक पार्क सहित अन्य स्थानों पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी।

कौमी भारत (23 अक्टूबर) के अनुसार भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी है। इस महिला आतंकी संगठन का नाम 'जमात उल-मोमिनात' रखा गया है। मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को इस संगठन का प्रमुख बनाया गया है।

सहाफत (22 अक्टूबर) के अनुसार पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई

के इशारे पर पंजाब के विभिन्न शहरों में सीरियल बम धमाके की साजिश को विफल बना दिया है। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान महकदीप सिंह और आदित्य के रूप में हुई है। इनके कब्जे से दो रॉकेट लॉन्चर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये हथियार विदेश में बने हुए हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों आरोपियों का संबंध हरप्रीत सिंह गुट से है। पंजाब पुलिस ने पिछले महीने फिरोजपुर से हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। अमृतसर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हरप्रीत सिंह ने उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए भर्ती किया था और उसी ने पाकिस्तान से रॉकेट लॉन्चर मंगवाकर उन्हें सौंपा था। अमृतसर की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर विवाद

उर्दू टाइम्स (23 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र के शहर पुणे स्थित ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित इस ऐतिहासिक स्थल पर नमाज अदा करने के आरोप में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि पुणे के शनिवारवाड़ा किले में कभी पेशवा शासक रहते थे और अब यह एएसआई के संरक्षण में है। भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने गोमूत्र छिड़ककर और पूजा करके उस स्थान का शुद्धिकरण किया जहां पर नमाज अदा की गई थी।

इस घटना के कारण राज्य की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में एक नया विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की प्रवक्ता रूपाली पाटिल थोम्बरे ने मेधा कुलकर्णी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने भाजपा से मांग की है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली इस सांसद पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने पुलिस से भी मांग की है कि वह मेधा कुलकर्णी के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करे। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता नीलम गोरहे ने कहा कि शनिवारवाड़ा एएसआई के संरक्षण में है और इसके कुछ नियम हैं। इन

नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस और जिलाधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वह सत्ता में है, इसलिए वह मनमानी कर सकता है।

दूसरी ओर, भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा है कि जिस स्थान पर मुस्लिम महिलाओं ने जुमा की नमाज अदा की वह एक ऐतिहासिक धरोहर है और एएसआई के संरक्षण में है। उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के इस कृत्य के विरोध में उस भूमि को पवित्र किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि शनिवारवाड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जिसमें नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई जाए।

हिंदुस्तान (21 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने पुणे के शनिवारवाड़ा में कुछ अज्ञात मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल पर नमाज पढ़ना निंदनीय है। राणे ने कहा कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुस्लिम महिलाएं यहां नमाज पढ़ती हैं तो कल को अगर कोई हिंदू मुंबई की हाजी अली दरगाह में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे या जय हनुमान का नारा लगाए तो मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि शनिवारवाड़ा हिंदू संस्कृति की एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे में वहां पर नमाज अदा करके माहौल खराब किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नमाज के लिए जगह की कमी है? अगर महिलाएं चाहतीं तो वे किसी भी मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस तरह की हरकत की। राणे ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजनीतिक कारणों से इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं ताकि राज्य की सांप्रदायिक सद्‌भावना बिगड़े।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि इन मुस्लिम महिलाओं ने शनिवारवाड़ा स्थित हजरत ख्वाजा सैयद शाह की दरगाह पर नमाज अदा की है, इसलिए इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पुलिस का दावा है कि नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद पतित पावन नामक एक हिंदूवादी संगठन ने इसकी लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने जिस दरगाह में नमाज अदा की है वह वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है। हैरानी की बात है कि अब हिंदू संगठन इस दरगाह और मजार को हटाने की मांग कर रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (22 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं पुणे स्थित ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा किले में टहलने गई थीं। तब नमाज का समय था, इसलिए उन्होंने वहां पर नमाज अदा की। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे मुद्दा बना लिया और विरोध-प्रदर्शन करते हुए इन मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा की सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने गोमूत्र छिड़ककर और पूजा करके उस स्थान का शुद्धिकरण किया। समाचारपत्र ने कहा है कि

पुलिस ने इन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की, यह समझ से परे है। नमाज पढ़ने से प्रदूषण, ट्रैफिक जाम या किसी की आजादी में बाधा नहीं आई। फिर विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया? समाचारपत्र ने कहा है कि यह राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का क्षेत्र है। वे पुणे जिले के प्रभारी मंत्री हैं। उन्हें इस मामले में फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन वे चुप रहे। नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज करना सरासर गलत है और यह एक वर्ग की धार्मिक गतिविधियों में अनुचित हस्तक्षेप है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं। यह समाज के हित में नहीं है।

हिंदुस्तान (22 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है वहां पर मुसलमानों को सुनियोजित ढंग से परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम दुश्मनी को हवा दी जा रही है। पिछले दिनों अहिल्यानगर (पूर्व में अहमदनगर) से एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक संग्राम जगताप ने हिंदुओं से अपील की थी कि वे दिवाली के अवसर पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करें। महाराष्ट्र में कट्टर भगवा तत्व लाख प्रयास करने के बावजूद अभी तक राज्य की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने में विफल रहे हैं। हालांकि, वे लगातार नफरत की ज्वाला भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

हाल ही में शनिवारवाड़ा परिसर में कुछ अज्ञात मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। अजीब बात है कि मुस्लिम दुश्मन मंत्री नितेश राणे ने जलती आग में घी डाल दिया। उन्होंने मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का सुझाव दे दिया। त्योहारों के अवसर पर महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भजन-कीर्तन व पूजा-पाठ का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान या ईसाई ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की। संतोष की बात यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल एनसीपी ने इस मुस्लिम विरोधी अभियान की निंदा की है। ■

औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव

कौमी भारत (27 अक्टूबर) के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेल विभाग के अनुसार यह कदम राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए उठाया गया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार इस परिवर्तन को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। स्टेशन के सभी साइनबोर्ड, टिकट, घोषणाएं और डिजिटल सिस्टम में नया नाम अपडेट किया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने 15 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी करके औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय से

मंजूरी मिलने के बाद उठाया था। शहर और रेलवे स्टेशन दोनों का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा राजवंश के द्वितीय शासक छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम मुगल शासन के दौरान रखा गया था। साल 1900 में हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया था।

इससे पहले राज्य सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था। महाराष्ट्र के एक बड़े वर्ग ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि मुगल बादशाह औरंगेजब ने छत्रपति संभाजी की निर्मम हत्या कर दी थी।

इसी समाचारपत्र में 26 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार महाराष्ट्र के सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। नाम परिवर्तन करने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दी थी। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2025 को इस्लामपुर नगर परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सांगली जिले का इस्लामपुर शहर अब ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन हेतु जनता ने जनांदोलन चलाया था। इस आंदोलन में मैंने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा कि यह सांगली और महाराष्ट्र की जनता के लिए गर्व का दिन है।

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बा मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 अक्टूबर को विश्व कल्याण आश्रम में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का तेजी से विकास किया जा रहा है। पुरानी सरकारें जनता के खून पसीने की धनराशि कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने पर खर्च करती थीं। जबकि हम वही धनराशि मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थानों के विकास पर खर्च कर रहे हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नाम बदलने की राजनीति का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के सचिव हाफिज उस्मान ने कहा है कि योगी सरकार राज्य में सांप्रदायिकता की ज्वाला भड़का रही है ताकि बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरा जा सके।

पाकिस्तान द्वारा भारत में उत्पात मचाने की साजिश

कौमी भारत (30 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सहयोग से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने और अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन देने का प्रयास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इसकी स्थापना पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के चार दिवसीय ढाका दौरे के बाद की गई है। जनरल मिर्जा ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से गुप्त मुलाकात की थी। बताया जाता है कि जनरल मिर्जा के साथ पाकिस्तानी सेना के एक दर्जन उच्चाधिकारी बांग्लादेश दौरे पर गए थे। इन्होंने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जासूसी तंत्र को मजबूत बनाने और आतंकवादियों की घुसपैठ से संबंधित योजनाओं पर भी विचार किया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों ने भारत के इन क्षेत्रों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों से भी संपर्क साधा है ताकि इन क्षेत्रों में अलगाववाद के आंदोलन को भड़काया जा सके।

इसी समाचारपत्र ने 28 अक्टूबर के अंक में दावा किया है कि हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक दर्जन आतंकवादी ढाका पहुंचे हैं। इनका नेतृत्व कुख्यात आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद का एक करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर ने किया। जहीर पाकिस्तान स्थित मरकजी जमीयत अहले हदीस और लश्कर-ए-तैयबा का महासचिव है। ये आतंकवादी 25 अक्टूबर को एक विशेष विमान से इस्लामाबाद से ढाका पहुंचे थे। इन्होंने बांग्लादेश की तब्लीगी जमात और जमात-ए-इस्लामी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की। इसके बाद इन्होंने राजशाही, नवाबगंज, चटगांव और मौलवी बाजार के सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की यह बांग्लादेश की दूसरी यात्रा है। यह भी जानकारी मिली है कि बांग्लादेश के

के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और वहां के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तुर्की के साथ सऊदी अरब के मॉडल पर सैन्य समझौता करने का आग्रह किया है। मुनीर के इस प्रस्ताव पर तुर्की का रुख सकारात्मक रहा है। आसिम मुनीर ने तुर्की में रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों का भी दौरा किया।

जेलों में बंद उल्फा के कुछ नेताओं को रिहा किया गया है और उन्हें गुप्त रूप से भारत भेजा गया है। लश्कर-ए-तैयबा असम, मणिपुर और त्रिपुरा में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है।

अवधनामा (28 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जॉर्डन का तीन दिवसीय दौरा किया है। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत हुई। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के सेना प्रमुख मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल-हुनेती से भी मुलाकात की। जानकार सूत्रों के अनुसार आसिम मुनीर ने जॉर्डन के शाह से अनुरोध किया है कि वे पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के मॉडल पर रक्षा समझौता करें ताकि अगर कोई देश जॉर्डन या पाकिस्तान पर हमला करता है तो दोनों देश हमलावर देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई कर सकें। बताया जाता है कि इस प्रस्ताव पर जॉर्डन का रुख सकारात्मक रहा है।

बीबीसी के अनुसार आसिम मुनीर ने हाल ही में तुर्की का भी दौरा किया है। मुनीर ने तुर्की

पाकिस्तान ने तुर्की से और अधिक संख्या में ड्रोन व रॉकेट खरीदने में रुचि दिखाई है। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने तुर्की में निर्मित ड्रोनों का इस्तेमाल किया था।

हिंदुस्तान (26 अक्टूबर) के अनुसार फिलिस्तीनी संगठन हमास ने पाकिस्तान में अपना एक नया केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र का प्रमुख नाजी जहीर को बनाया गया है। वह पाकिस्तान में हमास के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में पाकिस्तान में हमास की गतिविधियों में तेजी आई है। नाजी जहीर कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर कई रैलियों को संबोधित कर चुका है। 14 अक्टूबर को पेशावर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। हमास नेता खालिद मशाल ने वीडियो लिंक के जरिए इस रैली को संबोधित किया। इसी दौरान नाजी जहीर लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग की एक रैली में शामिल हुआ। यहां पर उसने इजरायल विरोधी नारे भी लगाए।

इस साल के जनवरी महीने में ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कद्दौमी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तब उसने पकिस्तानी संसद के

उच्च सदन सीनेट को भी संबोधित किया था। इससे पाकिस्तान और हमास के बीच गहरे संबंधों की पुष्टि होती है। 5 फरवरी 2025 को कश्मीर एकजुटता दिवस के अवसर पर हमास नेता नाजी जहीर, खालिद कद्दौमी और जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने एक विशाल रैली को संबोधित किया था। इस रैली में पाकिस्तानी सेना के उच्चाधिकारियों और पाकिस्तान के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी भाग लिया था। इसी तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें घोषणा की गई कि कश्मीर और फिलिस्तीन के मुजाहिदीन एकजुट हो चुके हैं। ये दोनों मिलकर कश्मीर को भारत के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ेंगे।

पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के खिलाफ अभियान

हमारा समाज (28 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश में रहने वाले अफगान मूल के 28 लाख नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक सात लाख से अधिक अफगान नागरिक अफगानिस्तान की सीमा में धकेले जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति किसी भी अफगान नागरिक को अपना मकान किराए पर देगा तो उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी भी अफगान नागरिक को नौकरी पर रखेगा तो उसे उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना, पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लाखों अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करके हिरासत केंद्रों में रखा है। देश के एक दर्जन से अधिक शहरों में अफगान शरणार्थियों के घरों और दुकानों को बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक पांच लाख मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। समाचारपत्र के अनुसार ये अफगान शरणार्थी पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से अपील की थी कि वह अफगान शरणार्थियों के निष्कासन अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे ताकि अफगान सरकार इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इसे नहीं माना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकार पिछले एक साल से इन अफगान शरणार्थियों को देश से निष्कासित करने का नोटिस दे रही है। अब उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थी न सिर्फ पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, बल्कि उनके कारण तस्करी और अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें देश में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाल ही में पाकिस्तान-अफगान सीमा के बंद किए जाने के कारण नौ लाख से अधिक अफगान शरणार्थी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना उन्हें शिविरों में रख रही है। इन अफगान नागरिकों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं कर रही है। वे खुले आसमान के नीचे नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

बांग्लादेश में जाकिर नाइक के स्वागत की तैयारी

हिंदुस्तान (28 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को बांग्लादेश दौरे की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश में जाकिर के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वह लगभग तीन सप्ताह तक बांग्लादेश में इस्लाम का प्रचार-प्रसार करेगा। जाकिर नाइक 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगा। इस दौरान वह देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक भाषण देगा। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार ने जाकिर नाइक के बांग्लादेश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जुलाई 2016 में ढाका में हुए आतंकवादी हमले के बाद जाकिर नाइक के 'पीस टीवी' चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद वह भारत छोड़कर भाग गया था। एक हमलावर ने बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार को बताया था कि उसे आतंकी हमले की प्रेरणा जाकिर नाइक के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित भाषणों से मिली थी। भारत में भी जाकिर नाइक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। इन दिनों वह मलेशिया में रह रहा है। भारत ने मलेशिया सरकार से कई बार यह मांग की है कि वह जाकिर नाइक को भारत के हवाले करे ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन मलेशिया सरकार ने ऐसा नहीं किया। जाकिर नाइक पाकिस्तान का भी दौरा कर चुका है। इस दौरे के दौरान वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकवादियों जैसे कमांडर मुज्जिमल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस और फैजल नदीम से भी मिला था। जाकिर नाइक ने लाहौर स्थित बादशाही मस्जिद में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद वह वहां से सऊदी अरब चला गया था।

चट्टान (23 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सेना के 15 उच्चाधिकारियों को

जेल भेज दिया है। इन अधिकारियों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में अपहरण, हत्या और हिरासत में यातना देने का आरोप है। आईसीटी ने 11 अक्टूबर को इन्हें मानवता का अपराधी करार दिया था। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायाधिकरण ने इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सेना में कार्यरत अधिकारियों को जेल भेजा गया हो। इसके अतिरिक्त आईसीटी के प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 20 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं।

उर्दू टाइम्स (30 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वह दिल्ली में स्वतंत्र, लेकिन सतर्क जीवन व्यतीत कर रही हैं। फिलहाल उनका इरादा भारत छोड़ने का नहीं है और न ही वे बांग्लादेश जाना चाहती हैं। सूचना के अनुसार दिल्ली में उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोली से मरने वाले लोगों के परिवारजनों से माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हिंसक प्रदर्शन देशद्रोही तत्वों द्वारा आयोजित किए गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को निर्देश दिया है कि वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करें।

पुर्तगाल में बुर्का पर प्रतिबंध

कौमी भारत (19 अक्टूबर) के अनुसार पुर्तगाल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है। इसके तहत देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह विधेयक दक्षिणपंथी पार्टी 'चेगा' ने पेश किया था। इस कानून में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब या बुर्का पहनने वालों के लिए 200 से चार हजार यूरो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का फिर से उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के साथ-साथ चार साल की जेल भी हो सकती है। इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को बुर्का या नकाब पहनने पर मजबूर करता है तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है।

गौरतलब है कि यूरोप के कई देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड में बुर्का

पहनने पर प्रतिबंध है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने कहा है कि हम अपनी बेटियों और आने वाली पीढ़ियों को बुर्का पहनने के दबाव से मुक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर, वामपंथी दलों ने इस कानून का विरोध किया है। उन्होंने इस कानून को मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करार दिया है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता पेड्रो नूनो सैंटोस ने कहा है कि किसी भी महिला को बुर्का पहनने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी अधिकार नहीं है कि कानून बनाकर मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करें। बता दें कि पुर्तगाल में बहुत कम मुस्लिम जनसंख्या है।

एतेमाद (22 अक्टूबर) ने पुर्तगाल में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस कानून का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं को उनके धार्मिक आचरण से रोकना है। समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि यूरोप में इस्लाम विरोधी माहौल में वृद्धि हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि यह कानून मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखने की साजिश है। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि मानवाधिकार संगठनों, धार्मिक संगठनों और पत्रकारों द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पुर्तगाल सरकार का यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देगा। समाचारपत्र ने लिखा है कि यूरोप में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। इससे वहां की ईसाई सरकारों में डर पैदा हो गया है। यही कारण है कि वे इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके इस्लाम के प्रसार को रोकना चाहते हैं। समाचारपत्र ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे यूरोप में इस्लाम के प्रति बढ़ती नफरत की भावना का विरोध करने के लिए एकजुट हों। अगर वे मूकदर्शक बने रहे तो ईसाई जगत से मुसलमानों और इस्लाम का नामोनिशान मिट जाएगा।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की जेल

कौमी भारत (22 अक्टूबर) के अनुसार पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस के 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को लीबिया के तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। फ्रांस के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा है। फ्रांस की विशेष पुलिस ने सरकोजी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की थी। इस जांच में पुष्टि हुई है कि 2007 में अपने चुनावी अभियान के दौरान सरकोजी ने गद्दाफी से गुप्त रूप से 35 मिलियन यूरो की राशि ली थी। उन्होंने इस धनराशि का

इस्तेमाल अपने चुनावी अभियान में किया था। गौरतलब है कि 2011 में गद्दाफी की मौत के बाद उनके बेटे सैफ अल-इस्लाम ने खुलासा किया था कि उनके पिता ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को एक मोटी धनराशि दी थी।

सरकोजी ने पत्रकारों को बताया कि यह आरोप बिल्कुल झूठा और राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वे इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील नहीं करेंगे और न्यायालय की साख की रक्षा के लिए जेल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें पेरिस की जेल के एक विशेष हिस्से में रखा गया है, जिसे वीआईपी सेक्शन कहा जाता है। वहां पर वे अपनी पांच साल की सजा काटेंगे। पेरिस अदालत के न्यायाधीश ने कहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने न्यायालय का सम्मान किया है। उन्होंने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के बजाय जेल जाना उचित समझा।

सरकोजी ने जेल जाने से ठीक पहले 'लॉ ट्रिब्यून डिमांचे' के संवाददाता को बताया कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। हालांकि, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं न्यायालय की साख के लिए इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे फ्रांस की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे और यह देश की प्रतिष्ठा के हित में नहीं होगा। इससे पहले 2011 में फ्रांस के एक अन्य पूर्व राष्ट्रपति जैक्स शिराक को भी अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था, लेकिन स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा गया था।

गाजा युद्धविराम समझौता खतरे में

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के बारे में जो लंबे-चौड़े दावे किए थे वे धूल में मिलते नजर आ रहे हैं। इजरायल और हमास के रुख के कारण यह समझौता खतरे में पड़ गया है। युद्धविराम के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं।

इंकलाब (21 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए गाजा पर भीषण बमबारी की है। इस बमबारी में 150 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके कारण युद्धविराम समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के लोगों का कहना है कि इजरायल के आक्रामक रुख को देखते हुए उन्हें युद्धविराम की संभावना नजर नहीं आती। युद्धविराम की घोषणा के बाद से इजरायल लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों में कम-से-कम 150 लोग मारे गए हैं। इजरायल का दावा है कि हमास ने उसके एक सैनिक की हत्या कर दी है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है।

अल जजीरा के पत्रकार हानी महमूद ने बताया कि फिलिस्तीनियों के हजारों शव मलबे में सड़ रहे हैं। दूसरी ओर, हमास का कहना है कि नि:शस्त्रीकरण की समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के लिए संघर्षशील विभिन्न गुटों में हथियार डालने को लेकर गंभीर मतभेद है।

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने दावा किया है कि हमास हथियार न डालने पर जोर दे रहा है, इसलिए कतर हमास पर युद्धविराम की शर्तों का पालन करने के लिए दबाव डाल रहा है।

इंकलाब (30 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा में हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठनों के सैन्य ठिकानों पर 30 से अधिक हमले किए हैं। इजरायली लड़ाकू विमान गाजा, रफा और खान यूनिस के क्षेत्रों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल के आक्रामक रवैये को देखते हुए उन्हें युद्धविराम की कोई संभावना नजर नहीं आती। अरब देशों ने गाजा पर हालिया इजरायली हमलों की निंदा की है। इस समझौते के मध्यस्थ देशों मिस्र और कतर ने कहा है कि इजरायल के इन हमलों के कारण शांति के प्रयास खतरे में पड़ गए हैं। जबकि जॉर्डन ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। अरब लीग ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वह

इन हमलों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन हैं।

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इजरायल एक स्वतंत्र देश है और हम अपनी रक्षा करना बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।

इंकलाब (24 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने वेस्ट बैंक में गिरफ्तारियों और आवासीय क्षेत्रों को बुलडोजरों से ध्वस्त करने का अभियान तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने रामल्लाह इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। इजरायल के उप-प्रधानमंत्री यारिव लेविन ने पुष्टि की है कि इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक से 32 विदेशी नागरिकों को निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वे इजरायली सेना पर हमला करने के लिए लोगों को भड़का रहे थे।

इंकलाब (24 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गाजा में युद्धविराम खतरे में है। यही कारण है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अचानक इजरायल का दौरा करना पड़ा है। इससे साफ है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के दबाव में युद्धविराम समझौते को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाचारपत्र ने जोर दिया है कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए गंभीर है तो उसे इजरायल पर सिर्फ जुबानी दबाव डालने के बजाय कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और उसे इजरायल को सैन्य सहायता देना फौरन बंद कर देनी चाहिए।

सियासत (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इजरायल द्वारा गाजा में युद्धविराम का उल्लंघन किए जाने पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने भय व्यक्त किया है कि इस क्षेत्र में फिर से युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है और इसकी पूरी जिम्मेवारी इजरायल के साथ-साथ अमेरिका पर होगी, क्योंकि वह युद्धविराम को लागू करवाने में विफल रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और इजरायल की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण गाजा शांति समझौता मिट्टी में मिलने वाला है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि ट्रम्प ने इस शांति समझौते को बहुत ही चतुराई से तैयार किया था ताकि हमास के निःशस्त्रीकरण के बाद इस पूरे क्षेत्र को इजरायल में शामिल किया जा सके। यह योजना ग्रेटर इजरायल का प्रथम चरण है।

एतेमाद (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नेतन्याहू की आक्रामक नीति के कारण गाजा युद्धविराम समझौता खतरे में पड़ गया है। इजरायली सेना युद्धविराम समझौते के बावजूद गाजा क्षेत्र पर लगातार हमला करके वहां के निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या कर रही है और अमेरिका मूकदर्शक बना हुआ है।

तुर्की द्वारा कुवैत, कतर और ओमान के साथ समझौते

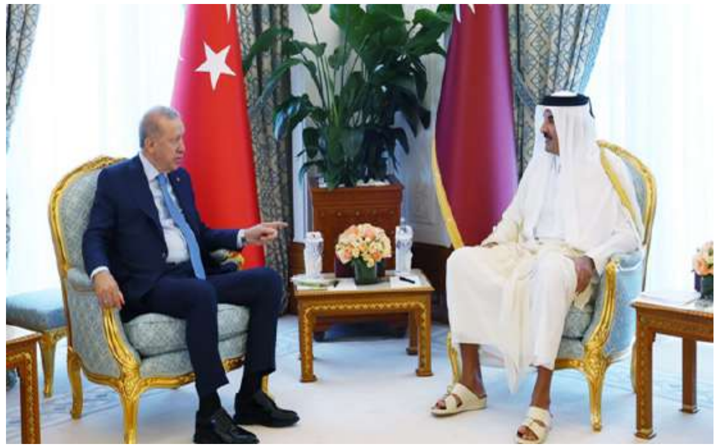

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तीन दिवसीय खाड़ी दौरे का समापन कर लिया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने कुवैत, कतर और ओमान के साथ 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तुर्की की मीडिया के अनुसार एर्दोगान ने यह दौरा खाड़ी देशों के शासकों के निमंत्रण पर किया था। इसका लक्ष्य इन देशों के साथ तुर्की के व्यापारिक और सैनिक संबंधों को मजबूत बनाना है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि एर्दोगान के इस दौरे की शुरुआत कुवैत से हुई थी।

कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल सबा ने एर्दोगान का स्वागत किया। दोनों देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और विश्व के मुस्लिम देशों के बीच बंधुत्व की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कुवैत के अमीर को तुर्की में निर्मित इलेक्ट्रिक कार भी भेंट की। कुवैत तुर्की में भारी पूंजी निवेश करेगा और कई नए उद्योग भी स्थापित करेगा।

इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कतर का दौरा किया। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और निवेश के साथ-साथ फिलिस्तीन के विकास में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने तुर्की-कतर उच्च रणनीतिक समिति की 11वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रणनीतिक विकास योजना और रक्षा उद्योग सहयोग समझौता प्रमुख हैं।

अंत में एर्दोगान ने ओमान का दौरा किया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने मस्कट स्थित अल आलम पैलेस में एर्दोगान का स्वागत किया। इस बैठक में खनिज उत्खनन, सैन्य सहयोग, औद्योगिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

एतेमाद (23 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की और कतर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने से संबंधित एक दर्जन समझौते हुए हैं। इन समझौतों पर तुर्की के व्यापार मंत्री उमर बोलात और कतर के व्यापार मंत्री शेख फैसल अल थानी ने हस्ताक्षर किए। एक अन्य समझौते पर तुर्की की रक्षा उद्योग एजेंसी के अध्यक्ष डॉ. हालुक गोरगुन और कतर के उप-प्रधानमंत्री शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने हस्ताक्षर किए।

तुर्की द्वारा विदेशों से लड़ाकू विमानों की खरीद

सियासत (28 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की ने ब्रिटेन और अमेरिका से भारी संख्या में लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। ब्रिटिश अखबारों के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर तुर्की की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह स्टार्मर की तुर्की की पहली आधिकारिक यात्रा है। तुर्की ब्रिटेन से 40 यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान खरीदेगा।

इजरायल और ग्रीस जैसे तुर्की के प्रतिद्वंद्वी देश अपनी वायुसेना की क्षमता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यही कारण है कि तुर्की अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक विमानों से लैस करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से उत्तरी साइप्रस का क्षेत्र ग्रीस और तुर्की के बीच प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बना हुआ है। किसी जमाने में इस क्षेत्र पर ग्रीस का प्रभाव था। बाद में साइप्रस के उत्तरी क्षेत्रों पर तुर्की के खलीफा ने कब्जा कर लिया था। तुर्की के खलीफा ने साइप्रस के जनसंख्या संतुलन को बदलने के लिए वहां पर रहने वाले ईसाइयों को उत्तरी साइप्रस से भागने पर मजबूर कर दिया और वहां पर भारी संख्या में अरबों को बसाया गया।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इस्लामी खिलाफत का पतन हुआ तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को ग्रीस के हवाले कर दिया, लेकिन यहां पर रहने वाले 40 प्रतिशत अरब ग्रीस के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तरी साइप्रस की मुस्लिम बहुल आबादी के तार तुर्की से जुड़े हुए हैं। तुर्की इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद इन प्रयासों में और भी वृद्धि हुई है। ग्रीस की वायु शक्ति का सामना करने के लिए तुर्की को विदेशों से नए लड़ाकू विमान खरीदने पर ध्यान देना पड़ रहा है। नाटो संधि में शामिल तुर्की इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह ब्रिटेन और अमेरिका से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे, इसलिए तुर्की ब्रिटेन से 40 यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान खरीद रहा है। जबकि अमेरिका से एफ-16 और एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदने हेतु बातचीत जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन तुरंत तुर्की को 12 यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएगा। ये विमान सऊदी अरब, ओमान कतर और कुवैत के पस भी हैं। जबकि 28 नए विमान अगले तीन सालों में तुर्की को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हो चुका है। इसकी मंजूरी यूरोफाइटर कंसोर्टियम के अन्य तीन देशों जर्मनी, इटली और स्पेन ने भी दे दी है।

सऊदी अरब द्वारा उमरा के लिए 40 लाख वीजा जारी

उर्दू टाइम्स (24 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब में उमरा का सीजन चल रहा है। इसमें भारी संख्या में विदेशी यात्री भाग ले रहे हैं। हज व उमरा मंत्रालय के अनुसार अब तक 40 लाख उमरा वीजा जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा वीजा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए हैं। जबकि इंडोनेशिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं, इराक चौथे और मिस्र पांचवें स्थान पर है। इस साल का उमरा सीजन जून 2025 में हज के तुरंत बाद शुरू हुआ था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उमरा वीजा लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। नुसुक पोर्टल के जरिए उमरा वीजा जारी किया जा रहा है। यूरोपीय देशों के यात्री भी इस साल के उमरा में विशेष रुचि ले रहे हैं। सऊदी अधिकारियों के अनुसार उमरा के लिए अधिकांश यात्री जेद्दा या सीधे मदीना पहुंचते हैं। वहां से वे अत्याधुनिक ट्रेन या बस से मक्का जाते हैं। सऊदी सरकार को यह आशा है कि 2030 तक उमरा अदा करने के लिए हर वर्ष तीन करोड़ लोग सऊदी अरब आएंगे।

एतेमाद (17 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने मक्का में एक विशाल परिसर विकसित करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त काबा में नमाज पढ़ने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। मक्का में 12 मिलियन वर्ग मीटर (लगभग 4.63 वर्ग मील) क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का नाम 'किंग सलमान गेट' रखा गया है। इस परियोजना का लक्ष्य हज और उमरा अदा करने वालों के लिए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करना है। मक्का स्थित मस्जिद अल-हरम तक पहुंच को आसान बनाने के लिए इस परियोजना को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 2036 तक तीन लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। गौरतलब है कि सऊदी सरकार हज और उमरा से हर वर्ष 12 अरब डॉलर की कमाई करती है। सऊदी सरकार तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पर्यटन और बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है।

सूडान के गृहयुद्ध में 1500 लोगों की मौत

सियासत (31 अक्टूबर) के अनुसार अफ्रीकी देश सूडान के शहर अल-फशर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हालिया हमलों में 1500 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने अल जजीरा को बताया कि पिछले डेढ़ साल से आरएसएफ और सरकारी सेना के बीच चल रही झड़पों में 14 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की और जॉर्डन ने सूडान के गृहयुद्ध में हो रहे नरसंहार की निंदा की है। मिस्र ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे फौरन युद्धविराम करें ताकि निर्दोष लोगों की हत्याओं को रोका जा सके। जबकि कतर और जॉर्डन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह सूडान में बिगड़ते हुए हालात को रोकने के लिए अविलंब हस्तक्षेप करे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने सूडान की घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए दोनों पक्षों से अनुरोध किया है कि वे फौरन युद्धविराम करें। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा है कि सूडान में डेढ़ लाख बच्चे भुखमरी के शिकार हैं और 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। सूडानी सेना और आरएसएफ इस युद्ध में लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2023 में सूडानी सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान और आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो के आपसी मतभेदों के कारण देश में गृहयुद्ध शुरू हो गया था।

अवधनामा (24 अक्टूबर) के अनुसार सूडान की राजधानी खार्तूम के हवाई अड्डे पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध में अब तक एक हजार लोग मारे जा चुके हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

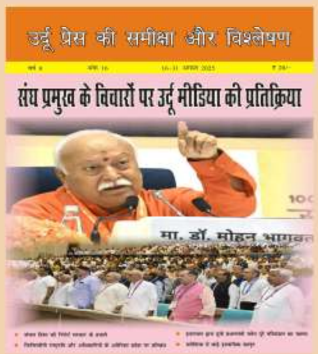

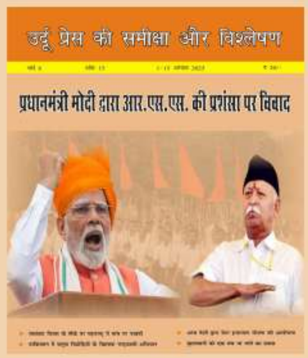

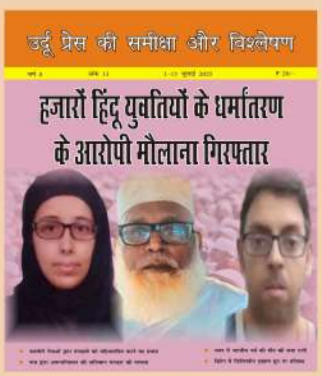

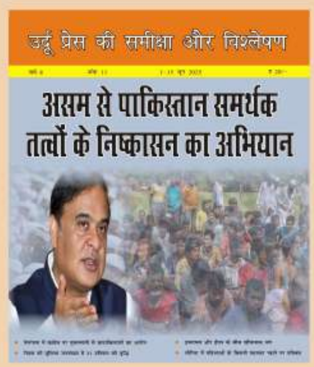

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in